Statment-I

List of major centrally sponsored Programmes Implemented in North-Eastern States During Eighth Five Year Plan is as under:—

1. Jawahar Rojgar Yojana (JRY)
2. Employment Assurance Scheme (EAS)
3. Million Wells Scheme (MWS)
4. Integrated Rural Development Programme (IRDP)
5. Training of Rural Youth for Self Employment (TRYSM)
6. Development of Women & Children in Rural Areas (DWCRA)
7. Indira Awaas Yojana (lAY)
8. Accelerated Rural Water Supply Programme (ARSWP)
9. National Social Assistance Programme (NSAP)

मध्य प्रदेश में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत खर्च की गई धनराशि

3945. **श्री अनन्तराय देवशंकर दुवे**: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 में इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में आवास निर्माण हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) 31 अक्तुबर, 1997 के अद्यतन स्थिति के अनुसार राज्य में उक्त योजना के अंतर्गत जिला-वार कितने आवासों का निर्माण किया गया;

(ग) राज्य में आवास समस्या के हल के लिए कितनी अनुमानित धनराशि की आवश्यकता है; और

(घ) आवास समस्या को कब तक हल कर लिए जाने की सम्भावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागगौड़ा पाटिल): (क) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण पर क्रमशः 113.85 करोड़ रुपए और 170.06 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

(ख) 1997-98 के दौरान 31 अक्तुबर, 97 तक निर्मित आवासों की जिलावार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) मंत्रालय द्वारा आवास समस्या के समाधान के लिए अपेक्षित समय और निधियों का राज्यवार मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, मंत्रालय के आकलन के अनुसार देश में ग्रामीण आवास की कमी को पूरा करने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 18,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।

विवरण

1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश में इंदिरा आवास योजना

जिले का नाम	31-10-97 तक निर्मित आवासों की संख्या (संख्या में)
बालाघाट	1326
बस्तर	6859
बेतूल	1080
भिंड	349
भोपाल	33
बिलासपुर	6795
दत्तरपुर	241
छिंदवाड़ा	1316
दमोह	271
दतिया	350
देवास	832
धार	853
दुर्ग	1031
पूठनिमाड़	697
गुना	809
ग्वालियर	446
होशंगाबाद	1478
इंदौर	79
जबलपुर	1625
झबुआ	714
मंडला	1417
मंदसौर	754
मुरैना	777
नरसिंपुर	508
पन्ना	275
रायगढ़	66
रायपुर	3585
रायसेन	534
राजगढ़	648

जिले का नाम	31-10-97 तक निर्मित आवासों की संख्या (संख्या में)
राजनंदगांव	937
रतलाम	1336
रीवा	843
सागर	1206
सतना	777
सिवनी	166
शहडौल	3012
शाजापुर	642
शिवहर	209
शिवपुरी	91
सिधी	2530
सरगुजा	5810
टिकमगढ़	611
उज्जैन	962
विदिशा	626
पश्चिम निमाड़	2708
कुल	58214

(175)

गरीबी-उन्मूलन

3946. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया**: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी दूर करने के लिए बेरोजगारी दूर करना जरुरी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने कि लिए इस समय अनेकों योजनाओं में परस्पर तालमेल न होने से उनका लाभ वांछित लोगों को नहीं मिल पा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन हेतु भविष्य में क्या-क्या सुधारात्मक कदम उठाने पर विचार किया है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबगौड़ा पाटिल): **(क) जी हां।**

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के लिए आबंटित धनराशियां

3947. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे**: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत महराष्ट्र को 1997-98 में कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई और इसमें से कितनी राशि खर्च हुई;

(ख) 1996-97 और 1997-98 में महाराष्ट्र राज्य में ऐसे कितने लोग गरीबी-रेखा से नीचे आंके गए थे जिसके आधार पर उक्त योजना के अंतर्गत धनराशि प्रदान की गई; और

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के संबंध में जिला-वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटिल): (क) से (ग) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निधियों को केन्द्रीय अंश देश के कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में राज्य/संघ क्षेत्र के ग्रामीण गरीबों की संख्या में अनुपात में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों करो आबंटित किया जाता है। 1996-97 और 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 1993-94 के सर्वेक्षण (एन.एस.एस.ओ.—43 वो दौर) के आधार पर योजना आयोग द्वारा किया गया गरीबी आकलन इस प्रयोजन के लिए लागू था। इस आकलन के अनुसार महाराष्ट्र में ग्रामीण गरीबों की जनसंख्या 166.90 लाख थी जो कि देश के कुल ग्रामीण गरीबों का 8.52% था।

राज्य से जिलों को आबंटन राज्य की कुल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की तुलना में जिले की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात तथा जिले में कृषि मजदूरों के प्रति व्यक्ति उत्पादन के व्यत्क्रमानुपात के आधार पर बनायी गई पिछड़ेपन की सूची से किए जाते हैं।

1997-98 के दौरान महाराष्ट्र में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गी तथा उपयोग की गई निधियों के जिला-वार ब्यौरे तथा पिछड़ेपन की सूची जो 1996-97 और 1997-98 के दौरान लागू थी, अनुबंध में है। [देखिए परिशिष्ट 184, अनुपत्र सं.]।